(f) whether State Government has submitted a number of Plans for setting up power projects with NRIs' assistance; and

(g) if so, whether clearance has been given to those projects?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) During April, 1993—January, 1994, Gujarat experienced a power shortage of 4.6 per cent as against 7.4 per cent for the country as a whole.

(b) and (c) The total installed capacity of Gujarat at the end of 6th Plan (as on 31-3-1985) was 3106.20 MW and the same at present (as on 28-2-1994) is 4934.67 MW. This is in addition to Gujarat's share in the Central Sector power projects installed in Western Region. The energy requirement in Gujarat stood at 26500 million units in 1992-93 which increased to 28990 million units in 1993-94.

(d) and ,e) The anticipated peaking shortage in Gujarat by the end of 8th Plan period is 1685 MW, after taking into account the new capacity addition envisaged during Eighth Five Year Plan.

The steps being taken to overcome the power shortage in the State of Gujarat include maximisation of generation from existing stations by increasing Plant Load Factor, renovation and modernisation programme, reduction in transmission and distribution losses, implementation of demand management and energy conservation measures, assistance from neighbouring system as and when available etc.

(f) and (g) Government of Gujarat have entrusted execution of Paguthan COGT (655 MW) in private sector by Gujarat Torrent Energy Corporation. The proposal has been cleared by Central Electricity Authority on 12-11-1993. They have also accepted 'in principle' the proposal of M/s Eisenberg Group of Companies, Israel, for setting up of a 250 MW Lignite Based TPS.

विदेशी सहायता से विद्युत परियोजनाओं का निर्माण

2193. **डा० जितेन्द्र कुमार जैन :**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 31 दिसम्बर, 1993 को देश में अनेक विद्युत परियोजनायें निर्माणाधीन थीं ;

(ख) यदि हां, तो विदेशी आर्थिक सहायता से निर्मित की जा रही परियोजनाओं की संख्या कितनी है ;

(ग) इन परियोजनाओं के निर्माण के लिये कुल कितनी विदेशी आर्थिक सहायता मिलने का निश्चय हुआ है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि विदेशी आर्थिक सहायता का समुचित उपयोग नहीं किया जा रहा है ;

(ङ) यदि हां, तो दिसम्बर, 1993 के अन्त तक ऐसी राशि कितनी थी, जिसे उपयोग में नहीं लाया गया था ;

(च) सरकार की अपनी वचनबद्धता के रूप में अन्य देशों को कुल कितनी राशि का भुगतान करना पड़ा था ; और

(छ) इन परियोजनाओं की कुल वार्षिक विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) से (छ) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। (नीचे देखिए)।

(घ) से (च) अन्य बातों से साथ-साथ विदेशी सहायता का धीमी गति से समुपयोजन किये जाने के मुख्य कारणों में ये शामिल हैं, विद्युत परियोजनाओं से क्रियान्वयन में विलम्ब समयावधिद्ध और लागत में वृद्धि होना, अपर्याप्त परि-

योजना तैयारी , क्रियान्वयन एजेंसियों की संगठनात्मक कमजोरी, प्रापण में विलम्ब, अपर्याप्त बजटीय सहायता तथा अन्य बाधाएं/भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में बाधाएं, पर्यावरणीय त्वीकृति और पुनर्वास योजनाएं आदि । दिसम्बर, 1993 के अंत तक विदेशी सहायता के रूप में 22688.22 करोड़ रुपये की राशि का समुयोजन किया गया था । 1993-94 के दौरान विद्युत परियोजनाओं के लिए आश्वस्त प्रभारों हेतु सरकार द्वारा भुगतान किए जाने वाली राशि 21.32 करोड़ रूपये होने का अनुमान है ।

विवरण

विदेशी सशायता से विद्युत परियोजनाओं के निर्माण से सम्बधित ब्यौरा

क्र०सं०	परियोजना का नाम/क्षमता मे० वा०	वित्तपोषण एजेंसी	विदेशी सहायता की राशि
1	2	3	4
	जल विद्युत परियोजनाएं		
1.	अपर इन्द्रावती (4+150) उड़ीसा	विश्व बैंक	213.030 मिलियन अमरीकी डालर
2.	कोयना चरण–4 (4+250) महाराष्ट्र	विश्व बैंक	320 मि० अमरीकी डालर
3.	कालीनदी चरण–2 (3+40+3+50) कर्नाटक	विश्व बैंक	197.2 मि० अमरीकी डालर
4.	शारावती टी० आर० (4+60) कर्नाटक	विश्व बैंक	130 मि० अमरीकी डालर
5.	लोअर ऐरिआर (3+60) कर्नाटक	विश्व बैंक	176 मि० अमरीकी डालर
6.	श्रीनगर (6+55) उत्तर प्रदेश	विश्व बैंक	47.048 मि० अमरीकी डालर
7.	नाथपा झाकरी (6+250) (मध्य प्रदेश)	विश्व बैंक	485.00 मि० अमरीकी डालर
8.	सरदार सरोवर (6+200+5+50) गुजरात	विश्व बैंक	300 मि० अमरीकी डालर
9.	वेस्टर्न यमुना कैनाल (2+6) हरियाणा	ओईसीएफ	300 मि० अमरीकी डालर
10.	उज्जैनी पीएसएस (11+2) महाराष्ट्र	ओईसीएफ	4000 मि० अमरीकी डालर

1	2	3	4
11.	घाटघर पीएसएस (2+125) महाराष्ट्र	ओईसीएफ	11414 मि. अमरीकी डालर
12.	सरदार सरोवर(6+200+5+50) गुजरात	ओईसीएफ	24646 मि० येन
13.	श्री सेलम एलबीपीएच (6+150) आन्ध्र प्रदेश	ओईसीएफ	26101 मि० येन
14.	इस्टर्न गण्डक कैनाल (3+5) बिहार	ओईसीएफ	1630 मि० येन
15.	तीस्ता कैनाल फाल्स (3+3+7+5) प० बंगाल	ओईसीएफ	8025 मि० येन
16.	लोअर बोरानी (2+50) (असम)	ओईसीएफ	1700 मि० येन
17.	चमेरा चरण 1 (3+160) हिमाचल प्रदेश	कनाडा	175.855 कनाडियन डालर
18.	दुलहस्ती (3+130) जम्मू एवं कश्मीर	फ्रेंच	2562.00 फ्रेंच फ्रेंक
19.	उरी (4+120) जम्मू एवं कश्मीर	स्वीडन	1480 स्वीडीश क्रोनर
ताप विद्युत परियोजनाएं			
1.	अनपारा "ख" (2+500) उत्तर प्रदेश	ओईसीएफ	14295 जापानी येन
2.	रायचुर-4 (1+210) कर्नाटक	ओईसीएफ	23142 जापानी येन
3.	बेसिन ब्रिज जो टी (4+30) तमिलनाडु	ओईसीएफ	11450 जापानी येन
4.	काठलगुड़ी सीसीजीटी (6+33+5+3+30) असम	ओईसीएफ	30000 जापनी येन
5.	गांधार गैस आधारित चरण-1+3+131 जीटी+1+255 एसटी) गुजरात	ओईसीएफ	13046 जापानी येन
6.	उराण डब्ल्यु एचआरपी (2+120) महाराष्ट्र	जर्मनी	310 डी एस
7.	येलहांका डी जी (6+21+32) केरल	फ्रेंच	304.74 एफ एफ
8.	दादरी सीसीजीटी (4+131 जीटी+ 2+146.5 एसटी) (उत्तर प्रदेश)	जर्मनी	484.90 डीएम
9	कहल गांव (4+210) बिहार	यूएसएसआर	219.16 यूएसएसआर रूबल
10.	रायलसीमा (2+210) आंध्र प्रदेश	विश्व बैंक	230 मि० अमरीकी डालर

11.	नार्थ मद्रास (2+210) एवं, (1+210) तमिलनाडु	विश्व बैंक	150 मि० अमरीकी डालर
12.	बजबज (2+250) प. बंगाल	एडीबी/आईएफसी/ सीडीसी/सप्लायर्स क्रेडिट	182 मि० अमरीकी डालर
13.	चन्द्रपुर–7 (1+500) महाराष्ट्र	विश्व बैंक	223 मि० अमरीकी डालर
14.	दहानु (2+250) बिहार	विश्व बैंक	268 मि० अमरीकी डालर
15.	ट्राम्बे सीसीटीपीपी (180) महाराष्ट्र	आईबीआरडी सीएचएफ	क 158 (अमरीकी डालर ख (17 स्वीस क्रेडिट) ग 15 डीएम
16.	नेशनल कैप एचरण–1 (4+210) उत्तर प्रदेश	विश्व बैंक	373 मि० अमरीकी डालर
17.	फरक्का चरण–2 (2+500) प. बंगाल	विश्व बैंक	238 मि० अमरीकी डालर 50.59 डीएम (जर्मनी) 159.93 डीएम (इटली)
18.	तलचेर चरण–1 (2+500) उड़ीसा	विश्व बैंक	367 अमरीकी डालर 536.34 एफ एफ

Proposals from private enterpreneurs wi h CEA

2199. SHRI BALBIR SINGH: Will the Minster of POWER be pleased to state:

(a) the names of the new power stations for which project reports were received in the Central Electricity Authority from private entrepreneurs during the last two years;

(b) the project reports cleared by the Central Electricity Authority for implementation without stipulating any conditions; and

(c) the precise nature of the principal stipulations made by the Central Electricity Authority in each case?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) The names of 23 private power projects for which the project reports have been received in the Central Electricity Authority during the last two years are given in the enclosed statement-I (*See* below).

(b) Six private power projects have been cleared during the last two years by the Central Electricity Authority subject to certain conditions.

(c) The details of conditions stipulated by CEA while according their clearance to the six private power projects is given in the enclosed statement-II.